



An e-Governance Newsletter of
NIC RAJASTHAN

त्रैमासिक डिजिटल समाचार पत्र (जनवरी से मार्च 2025)

हमारी विरासत



एकलिंगनाथ मंदिर

<https://devasthan.rajasthan.gov.in/images/udaipur/eklingji.htm>

एकलिंगनाथ महादेव या एकलिंगजी मंदिर, राजस्थान के उदयपुर शहर से 23 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इस स्थान पर 108 मंदिर हैं, जिनमें सबसे बड़ा आकर्षण 1300 साल पुराना, सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध श्री एकलिंगनाथ महादेव (भगवान शिव) का मंदिर है। अरावली की पहाड़ियों और जंगल भगवान के लिए आदर्श निवास स्थान हैं। श्री एकलिंगजी मेवाड़ के शासक महाराणाओं के कुल देवता हैं। महाराणा बप्पा रावल ने 734 ई. में मंदिर का निर्माण कराया और बाद में इसे आगे के महाराणाओं द्वारा विस्तारित और रखरखाव किया गया। बप्पा रावल भगवान शिव के एक उत्साही भक्त थे और उन्होंने अपनी सारी सफलता का श्रेय श्री एकलिंगनाथ को दिया। इसलिए, महाराणा परिवार आज भी एकलिंगजी को अपना कुल देवता मानता है और भगवान शिव, मेवाड़ रियासत के राजा और महाराणा को राज्य का दीवान (मंत्री) भी मानता है।

एकलिंगजी की सुंदर चतुर्मुखी मूर्ति काले संगमरमर से तैराशी गई है। पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी मुख क्रमशः भगवान ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवलिंग इन चार मुखों के बीच में स्थापित है। इन चार मुखों के सामने चार द्वार हैं। पूर्वी द्वार की ओर देवी पार्वती, पास में गणेशजी, दक्षिणी द्वार पर गंगाजी, पास में कार्तिकेयजी की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। इस मंदिर में भगवान शिव का पूरा परिवार देखने को मिलता है। मंदिर में दो मंजिला बरामदा है। मंदिर के टॉवर और दीवारों पर नक्काशी जटिल और आश्चर्यजनक है। मंदिर 50 फीट ऊंचा है और इसकी त्रिज्या लगभग 60 फीट है। टॉवर सफेद संगमरमर से बना है। मंदिर परिसर में अन्य मंदिर यमुना, सरस्वती, अंबामाता, गणेशजी और कालिकादेवी हैं मंदिर में दो खूबसूरत कुंड या पवित्र तालाब हैं जिन्हें तुलसी और पार्वती कुंड के नाम से जाना जाता है। मंदिर के दक्षिणी हिस्से में कुल-गुरुओं की समाधि स्मारक हैं। विशेष अवसरों पर महाराणा स्वयं भगवान की पूजा करते हैं।

एकलिंगजी में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार महाशिवरात्रि है। यह दो दिनों तक बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। मंदिर समय अनुसार खुलता व बंद होता है व दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय शाम को 7:00 से 7:30 बजे के बीच होने वाली आरती के दौरान होता है। यहां पर पूजा सामग्री बेचने वाली दुकानें व रेस्तरां हैं और ठहरने के लिए आस-पास, धर्मशालाएँ और होटल उपलब्ध हैं। मंदिर सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, और सरकारी बसें मंदिर तक पहुंचती हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन उदयपुर है, जो 25 किमी दूर स्थित है, जबकि निकटतम हवाई अड्डा डबोक है, जो मंदिर से 40 किमी दूर है।

महत्वपूर्ण आयोजन / घटनाएँ

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार, 18 जनवरी 2025 को नई दिल्ली से एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत पूरे भारत में 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए और विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों से बातचीत की। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन तकनीक से भूखंड का मानचित्रण करके ग्रामीण क्षेत्र में स्थित घर के मालिकों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। राजस्थान राज्य में लगभग 1.5 लाख लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड और पट्टे दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री ने श्रीगंगानगर जिले की एक लाभार्थी रचना से बात की, जिसने अपने अनुभव और स्वामित्व कार्ड प्राप्त करने के लाभों को साझा किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान से एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान के सभी जिले माननीय पीएम के लाइव कार्यक्रम से जुड़े रहे व जिला स्तर पर स्थानीय समारोह आयोजित किया गया जिसमें राज्य मंत्री, जिला कलेक्टर, महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों और लाभार्थियों की उपस्थिति में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण किया गया। एनआईसी राजस्थान के सभी डीआईओ/जिला केन्द्रों ने जिला प्रशासन से समन्वय कर तकनीकी रूप से कार्यक्रम को सफल बनाया और वास्तविक कार्यक्रम से एक दिन पहले कार्यक्रम के परीक्षण/ड्राई-रन के साथ स्थल पर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की। एक इंटरैक्टिव साइट होने के कारण, एनआईसी श्रीगंगानगर बहुत अधिक केन्द्रित था व एनआईसी राजस्थान के वीसी डिवीजन के समन्वय में कार्यक्रम को सफल बनाया गया। स्वामित्व पोर्टल वेबसाइट का लिंक है: <https://svamitva.nic.in/>

माननीय प्रधानमंत्री का किसान सम्मान निधि लाइव कार्यक्रम

24 फरवरी, 2025 को भागलपुर, बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीएम-किसान योजना के तहत 19वीं किस्त जारी की गई। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता जारी होने से देश भर के किसानों को लाभ हुआ। राजस्थान में, 4 जिलों - अजमेर, अलवर, बीकानेर और जोधपुर ने भाग लिया और वर्चुअल मोड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम से जुड़े। इन जिलों के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (डीआईओ) ने जिला कृषि विभाग के साथ समन्वय किया, कार्यक्रम स्थल का दौरा किया, मुख्य और बैकअप लीज लाइन के साथ कनेक्टिविटी का परीक्षण किया और कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए तकनीकी सहायता सुनिश्चित की।



माननीय मुख्यमंत्री ने ई-वर्क 2.0 सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप लॉन्च किया



<https://tdprwms.rajasthan.gov.in/>

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने 27 मार्च 2025 को भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ग्रामीण विकास विभाग के लिए NIC राजस्थान द्वारा विकसित ई-वर्क 2.0 सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नए सॉफ्टवेयर में माप पुस्तिका ऑनलाइन भरने और कार्य एजेंसियों को ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। मोबाइल ऐप के माध्यम से विधायक कार्यों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यों की स्थिति देख सकेंगे, जबकि अधिकारी कार्यों के वास्तविक समय के निरीक्षण को रिकॉर्ड कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल और ऐप को NIC-ग्रामीण विकास टीम द्वारा श्री जितेंद्र कुमार वर्मा, SIO NIC राजस्थान के निर्देशन में विकसित किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और शिक्षा ऐप सुविधाओं का शुभारंभ

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने शिक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तीन प्रमुख ऐप सुविधाओं के साथ छात्रों के लिए यूनिफॉर्म और बैग डीबीटी लॉन्च किया। इनमें शामिल हैं - छात्र उपस्थिति - बेहतर निगरानी के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग, मौखिक पठन प्रवाह (ओआरएफ) मूल्यांकन - मूलभूत साक्षरता को मजबूत करना और प्रवेशोत्सव - स्कूल नामांकन को बढ़ावा देना। यूनिफॉर्म और बैग डीबीटी के तहत, पे मैनेजर पर 35 लाख छात्रों के बिल तैयार किए गए और 22 लाख से अधिक छात्रों को भुगतान पहले ही संसाधित किया जा चुका है। SIO राजस्थान के मार्गदर्शन में एनआईसी शिक्षा टीम के प्रयासों से, स्कूली शिक्षा कुशल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-संचालित शासन की ओर बढ़ रही है।



<https://rajshaladpwn.rajasthan.gov.in>

एनआईसी के महानिदेशक (डीजी) का जयपुर दौरा



DG NIC Welcomed by SIO Rajasthan

DG NIC Meets CS Rajasthan

DG NIC Meets ACS Jaipur

DG, NIC reviewed ongoing initiatives with SIO & DDO DG, NIC visited Bhambash State Data Centre, Jaipur

महानिदेशक (डीजी) एनआईसी, श्री इंद्र पाल सिंह सेठी ने 27-28 मार्च 2025 को राजस्थान आईटी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर का दौरा किया। श्री जितेंद्र कुमार वर्मा, SIO एनआईसी राजस्थान ने डीजी, एनआईसी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान, डीजी एनआईसी ने नवाचार और दक्षता के लिए भारत एआई मिशन के तहत आईसीटी पहलों पर राजस्थान के मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत, आईएसएस के साथ चर्चा की। उन्होंने श्री अखिल अरोड़ा, IAS, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) से भी मुलाकात की और राजस्थान में ई-गवर्नेंस प्रदान करने वाली विभिन्न परियोजनाओं में NIC/NICSI की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने SIO और DIO के साथ एनआईसी परियोजनाओं और चल रही पहलों की समीक्षा करने, उनके योगदान की सराहना करने और डिजिटल गवर्नेंस को और मजबूत करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एनआईसी राजस्थान राज्य केंद्र का दौरा किया।

महत्वपूर्ण आयोजन / घटनाएँ

राजस्थान आईटी दिवस मनाया

राजस्थान आईटी दिवस 27-28 मार्च 2025 को जयपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में मनाया गया। एनआईसी राजस्थान ने आईटी एक्सपोजे में भाग लिया और अपने आईटी उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए पहचान और संस्था आधार के फ्लेक्स से सुसज्जित एनआईसी स्टॉल की स्थापना की। एनआईसी स्टॉल राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निचले तल पर स्थित थी और इसका दौरा महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। इनमें शामिल थे - श्री सुधांशु पंत, आईएएस, राजस्थान के मुख्य सचिव, श्री इंद्र पाल सिंह सेठी, महानिदेशक (डीजी) एनआईसी और श्री पी.के. मित्तल, डीडीजी और एचओजी, डेटा गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजी डिवीजन (डीजीएसडी), एनआईसी मुख्यालय आदि। सभी गणमान्य व्यक्तियों ने राज्य सरकार के साथ समन्वय में आईटी की कार्यान्वयन हेतु एनआईसी राजस्थान के प्रयासों तथा इसके आईटी उत्पादों की सराहना की। महानिदेशक, एनआईसी ने 28 मार्च 2025 को राजस्थान आईटी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और माननीय मंत्री (आईटी), कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और श्रीमती अर्चना सिंह, सचिव और आयुक्त, डीओआईटी/एडसी, राजस्थान के साथ मंच साझा किया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, डीजी एनआईसी ने राजस्थान भर में डिजिटल परिवर्तन में एनआईसी की आईटी पहल की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अपने सुझाव साझा किए। श्री पी.के. मित्तल, डीडीजी और एचओजी ने आईटी दिवस के दौरान डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पर एक प्रस्तुति दी।

राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जयपुर में राजस्थान आईटी दिवस समारोह 2025 की झलक



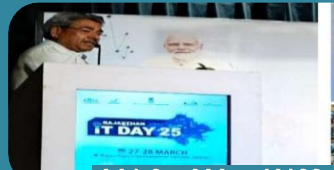
महानिदेशक एनआईसी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया



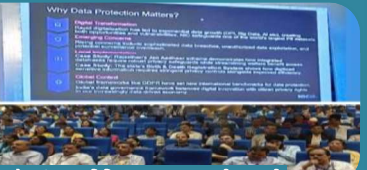
एनआईसी स्टॉल पर मुख्य सचिव राजस्थान एसआईओ राजस्थान के साथ



महानिदेशक एनआईसी ने एनआईसी स्टॉल का दौरा किया, अधिकारियों से बातचीत की और स्टार्टअप नवाचारों की जानकारी दी



श्री पी.के. मित्तल डीडीजी एनआईसी ने डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पर जानकारी साझा की



आईटी एक्सपोजे में टीम एनआईसी राजस्थान



राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का कार्यान्वयन

<https://raj.neva.gov.in>



राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) एक केंद्रीय परियोजना है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली द्वारा "एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन" पहल के तहत विकसित किया गया है। राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष (आरएलए) ने विधानसभा में नेवा को लागू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) एक कार्य प्रणाली है जिसे सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में सदन के अध्यक्ष की सहायता करने, माननीय सदस्यों को अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में सक्षम बनाने और सदन के विधायी कार्यों को कागज रहित व सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेवा परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एनआईसी राजस्थान द्वारा विधानसभा (आरएलए) के समन्वय में तैयार की गई और माननीय अध्यक्ष के साथ विभिन्न बैठकों के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया गया। नेवा परियोजना के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे की सुविधा के लिए आरएलए को लैन, आईपेड, पीसी, लेपटॉप और अन्य हार्डवेयर की आवश्यकताओं का विवरण देने वाला एक व्यापक विन्यास प्रदान किया गया था। राजस्थान विधानसभा से बहुत सारा डेटा - जिसमें प्रश्न, प्रस्ताव/नोटिस, सदस्यों के प्रोफाइल, बिल और सदन की कार्यवाही शामिल है - सफलतापूर्वक नेवा सिस्टम में स्थानांतरित कर दिया गया है। सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु नेवा टीम को निर्धारित डेटा लगातार प्रदान किया गया।

सड़क सुरक्षा पर कौशल संवर्धन कार्यक्रम

<https://rad.parivahan.gov.in>



राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए), जयपुर ने 23-24 जनवरी 2025 को आरपीए परिसर में सड़क सुरक्षा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया। एनआईसी को इंटेलेजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) और ईटीप्रेडेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस / इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट से संबंधित प्रौद्योगिकी प्रगति पर प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया गया, जो ई-ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काफी उपयोगी हैं। श्री श्रीपाल यादव, वैज्ञानिक-एफ और एनआईसी राज्य ई-ट्रांसपोर्ट समन्वयक ने दोनों प्लेटफॉर्म पर विस्तृत व लाइव प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसमें विभिन्न हितधारकों को इनके उद्देश्यों, प्रक्रियाओं, उपयोगों और परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। श्री एस सेगाथिर आईपीएस, एडीजीपी सह निदेशक आरपीए, श्री गौरव भार्गव आईपीएस, एडिशनल निदेशक-आरपीए, एडिशनल एसपी, आरजेएस व आरपीएस के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस वार्डन, न्यायिक प्रशिक्षु, पुलिस मित्र, एनसीसी के डेटेड, एनजीओ और अन्य की अनुग्रहपूर्ण उपस्थिति रही। जागरूकता फैलाने व सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कौशल संवर्धन कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

महत्वपूर्ण आयोजन / घटनाएँ

राजस्थान विधानसभा में 2025-2026 के लिए पहला पेपरलेस ग्रीन बजट पेश किया गया



आईएफएमएस-बजट एप्लीकेशन एनआईसी राजस्थान द्वारा विकसित है व इसकी एक विशिष्ट सुविधा ने राजस्थान की माननीय उपमुख्यमंत्री (वित्त) श्रीमती दीपा कुमारी को राजस्थान का पहला पेपरलेस ग्रीन बजट तथा राज्य बजट पेश करने में मदद की। आईएफएमएस-बजट 3.0 एप्लीकेशन को एनआईसी वित्त टीम द्वारा एंगुलर, जावा व ओरेकल में माइक्रोसर्विस आधारित आर्किटेक्चर के साथ उभरती हुई तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया गया। माननीय उपमुख्यमंत्री (वित्त) के भाषण के साथ पूरा बजट दस्तावेज सभी माननीय सदस्यों और आम जनता को एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराया गया। बजट मोबाइल ऐप को एनआईसी द्वारा उभरती हुई तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया गया ताकि बजट दस्तावेजों व भाषणों तक पहुंच आसान हो सके। एंड्रॉइड ऐप का लिंक: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifms.budget.rajasthan> आईओएस ऐप का लिंक: <https://apps.apple.com/in/app/budget-rajasthan/id1552876302>

एनआईसी राजस्थान में 1 से 15 फरवरी 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया

एनआईसी मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, एनआईसी राजस्थान में 1 से 15 फरवरी 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। एनआईसी राजस्थान द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान एनआईसी राज्य केंद्र, परियोजना कार्यालयों और जिला केंद्रों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के लिए स्वच्छता कार्य योजना तैयार कर, प्रसारित की गई। स्वच्छता पखवाड़ा एनआईसी के सभी अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालयों में स्वच्छता शपथ समारोह के साथ शुरू हुआ। इसके दौरान की जाने वाली विभिन्न दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में एनआईसी कार्यालय व परिसर की सामान्य सफाई, कॉमन क्षेत्र, साइट बिल्डिंग, शौचालय की सफाई, आवश्यक स्थानों पर कूड़ेदान रखना, श्रमदान, वृक्षारोपण, प्राकृतिक सौंदर्यकरण, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सर्वर, वीसी सिस्टम, नेटवर्क रैक आदि सहित सामान्य व तकनीकी स्टोर की सफाई शामिल है। इसके अलावा कार्यालयों से पुरानी फाइलें / रजिस्टर हटा दिए गए, साथ ही अनुपयोगी फर्नीचर और पॉलीथीन विरोधी अभियान शुरू किया गया। एनआईसी राजस्थान के सभी कार्यालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-कचरा प्रबंधन और स्वच्छता पर जोर देते हुए "स्वच्छता - हर किसी का व्यवसाय" पर श्री विनोद शर्मा, डीआईओ और वैज्ञानिक ई द्वारा दिए गए व्याख्यान में भाग लिया। सभी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियों की तस्वीरें एनआईसी राजस्थान के मीडिया प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस) पोर्टल व स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) पोर्टल पर अपलोड की गई।



डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला



डेटा गवर्नंस एंड स्ट्रेटेजी डिवीज़न (डीजीएसडी), NIC मुख्यालय, श्री प्रशांत कुमार मिश्र, डीजी व एचओडी-डीजीएसडी की अध्यक्षता में, सोमवार 17 मार्च 2025 को कॉन्फ्रेंस हॉल, मुख्य भवन, सचिवालय, जयपुर में "गोपनीयता के लिए - आईटी अनुप्रयोगों में चर्चा और कार्यान्वयन" शीर्षक से एक राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य राज्य के 11 अधिकारियों को डीपीडीपी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के बारे में जानकारी देना था व यह बताना था कि आईटी अनुप्रयोगों में किस तरह से चीजों को संबोधित करने की आवश्यकता है। कार्यशाला के दौरान, डीजी व एचओडी-डीजीएसडी और उनकी टीम ने राज्य स्तर पर बेहतर डेटा सुरक्षा के साथ एक सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल पाइपलाइन तंत्र बनाने के लिए प्रमुख डेटा गवर्नंस सिद्धांतों, अनुपालन रणनीतियों और शासन की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया। राज्य सरकार और एनआईसी के 100 से अधिक अधिकारियों ने सत्र में शारीरिक रूप से या वीसी के माध्यम से भाग लिया, जिससे भारत के किस तरह हो रहे डेटा गवर्नंस परिदृश्य की व्यापक पहुंच और बेहतर समझ सुनिश्चित हुई। कार्यशाला के पहले सत्र में डीपीडीपी अधिनियम 2023 और मसौदा डीपीडीपी नियम 2025 को समझने पर जोर दिया गया, जबकि दूसरे सत्र में राज्य आईटी विभाग के लिए रणनीतियों को लागू करने और डेटा न्यूनीकरण, सहमति प्रबंधन और शासन ढांचे में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा की गई।

राजहैल्थ पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य संसाधन प्रबंधन



राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 7,674 नर्सिंग अधिकारियों की पदस्थापना की प्रक्रिया राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से जनवरी 2025 में पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूर्ण कर ली गई। यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों द्वारा अपने पसंदीदा पदस्थापन स्थान के संबंध में वरीयता भरने के साथ प्रारंभ होती है व विभाग द्वारा पदस्थापन स्थान का अंतिम आवंटन किया जाता है। पदस्थापना के पश्चात पदस्थापित नर्सिंग अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं भी पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जाएंगी। सम्पूर्ण प्रक्रिया राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूर्ण की गई। वेबसाइट - <https://rajhealth.rajasthan.gov.in>

Posting Work Flow of "Health Resource Management" in RajHealth Portal	
1. Initiate the Posting process	9. Online Generation of e-signed posting order
2. Automatic vacancy generation	10. Self-declaration and joining through RajHealth by individual candidate
3. Provision to freeze office/health institution wise vacancies	11. Uploading the desired documents through RajHealth by the candidate
4. Automatic intimation to candidates through SMS to fill their choices for posting	12. Online document verification by respective CHMOs/PMOs
5. Updation of personal details by candidates before online submission of choices	13. Joining of nursing officers was displayed on the RajHealth portal to the concerned CHMO/PMO/Superintendent for Approval and intimation to candidate through SMS after joining confirmation.
6. Filling of Choices & online undertaking by the candidates	14. Real time availability of monitoring reports to track the status of joining at different administrative levels.
7. The round wise allocation of health facilities based on the filled choices.	

विशेष आयोजनों पर एक नज़र



पाकिस्तानी तीर्थयात्री 5 जनवरी 2025 को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के श्रद्धेय उर्स में भाग लेने के लिए अजमेर पहुंचे और 11 जनवरी 2025 तक वहां ठहरे। एनआईसी जिला केंद्र, अजमेर ने पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों के सी-फॉर्म ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि और 5 से 11 जनवरी, 2025 के दौरान ठहराव स्थल से उनके आवागमन की 24 घंटे निगरानी के लिए सीआईडी स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया, जो एनआईसी अजमेर द्वारा पूर्व में विकसित वेब-आधारित "तीर्थयात्री सूचना प्रणाली" के माध्यम से संचालित हुआ।



21 मार्च 2025 को श्री रामावतार मीना, आईएस, कलेक्टर और डीएम, झुंझुनू द्वारा एनआईसी जिला केंद्र झुंझुनू का नवीनीकरण कार्यों की समाप्ति के बाद पुनर्उद्घाटन किया, जो उत्कृष्टता और नवाचार के लिए एक नई प्रतिबद्धता को दर्शाता है व विस्तार, आधुनिकीकरण, रीब्रांडिंग और एनआईसी समर्पण की मजबूती का प्रतीक है। उद्घाटन समारोह के दौरान जिला कलेक्टर के अधिकारी व कर्मचारी, जिला स्तरीय अधिकारी और डीओआईटी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET), प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए एक राज्य स्तरीय परीक्षा, 27-28 फरवरी 2025 को आयोजित की गई। REET परीक्षा पर डिजिटल नज़र रखने के लिए NIC जिला केंद्रों पर एक जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। NIC के तकनीकी और नेटवर्किंग सहयोग के साथ व DIO NIC के समन्वय से जिला प्रशासन द्वारा लाइव निगरानी की गई। REET केंद्रों में लगाए गए लाइव IP कैमरों के साथ-साथ इस्तेमाल किए गए वाहन की GPS ट्रैकिंग द्वारा निगरानी की गई।



त्रैमासिक प्रोजेक्ट - स्थानीय निकायों के खातों का आर्थिक और उद्देश्य वर्गीकरण



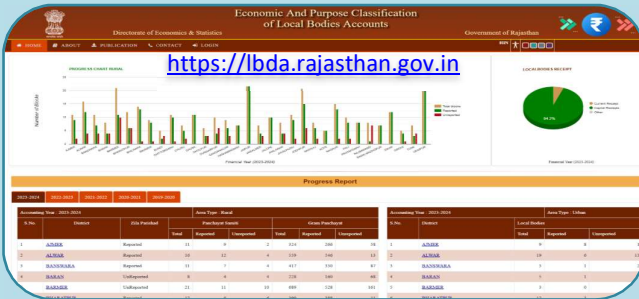
श्री अमित अग्रवाल
वैज्ञानिक-एफ,
राजस्थान राज्य केंद्र

एनआईसी राजस्थान द्वारा विकसित, स्थानीय निकाय लेखा (एलबीडीए) एप्लीकेशन राजस्थान सरकार की पहल है, जिसके तहत राज्य के सभी स्थानीय निकायों के वर्गीकृत खाते बनाए जाते हैं। पोर्टल पिछले 10 वर्षों से राजस्थान में संचालित है। पोर्टल सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के वर्गीकृत खातों को संकलित करता है, जिसमें ग्राम पंचायत समितियाँ, और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, जिला परिषद शामिल हैं, जिन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है -

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुमान में स्थानीय निकायों का क्षेत्रवार योगदान और जीएसडीपी की गणना में उपयोग उत्पन्न करना।
- राज्य सरकार को नीति निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराना।
- प्राप्तियों/व्यय का राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायतवार विश्लेषण।
- प्रशासनिक विभागों के लिए आय और व्यय खाते।
- स्थानीय निकायों के पूंजी वित्त खाते एवं उधार खाते।
- लोक प्रशासन से शुद्ध उत्पाद का अनुमान।
- विभागीय उपक्रमों का चालू व्यय एवं शुद्ध उत्पाद।
- पूँजी निर्माण प्रशासन।

स्थानीय निकाय लेखा पोर्टल पिछले 10 वर्षों से NIC राजस्थान के तकनीकी मार्गदर्शन में विकसित और कार्यान्वित किया जा रहा है। पोर्टल जिलों और ब्लॉक कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ सभी स्थानीय निकायों के वर्गीकृत खातों को तैयार करने में मदद करता है। यह पोर्टल MoSPI को प्रस्तुत करने के लिए वर्गीकृत खातों के समय पर संकलन में अत्यंत सहायक है। MoSPI द्वारा इस प्रणाली की सराहना की गई है और इसे मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझा किया गया है। मैं इस प्रणाली को डिजाइन करने और विकसित करने के लिए NIC राजस्थान टीम को बधाई देता हूँ।

श्री विनेश सिंघवी
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
(सांख्यिकी विभाग), राजस्थान



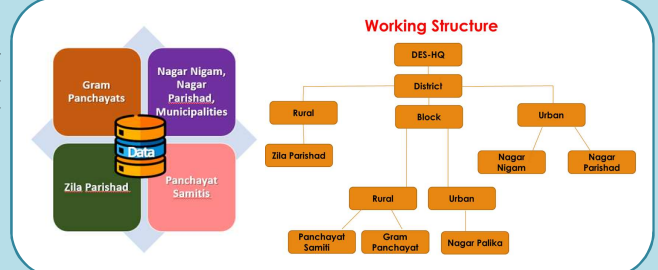
- एलबीडीए पोर्टल से पहले, संकलन कार्य मैनुअल रूप से किया जाता था। जिसमें केवल 30% से 40% परिणाम प्राप्त होते थे, लेकिन अब पोर्टल के साथ इसमें काफी सुधार हुआ है। अब 90% परिणाम प्राप्त होते हैं। परिणामों की शेष पूर्णता गुणक विधि के माध्यम से प्राप्त की जाती है।
- गुणक रिपोर्ट, इस प्रकार, एलबीडीए पोर्टल की एक अनूठी विशेषता है।
- 10% अनुसूचियों (यादृच्छिक रूप से चयनित) की जांच जिला कार्यालय में की जाती है।
- डीईएस-मुख्यालय एलबीडीए पोर्टल की निगरानी करता है, जिसमें समय-समय पर अनुसूचियों की जांच, तैयार रिपोर्ट, त्रुटि रिपोर्ट, गुणक रिपोर्ट आदि की निगरानी की जाती है।
- पोर्टल को भारत सरकार में प्रस्तुत किया गया व कई राज्य इसे अपने यहाँ लागू करने के इच्छुक हैं।

मध्य प्रदेश में पोर्टल की प्रतिकृति

मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अनुरोध पर वर्गीकृत खाता बनाने के लिए पोर्टल को मध्य प्रदेश के साथ साझा किया गया है। पोर्टल का प्रशिक्षण डीईएस, मध्य प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया। डीईएस के लिए राज्य में पोर्टल को लागू करने के लिए तकनीकी ज्ञान भी एनआईसी राज्य केंद्र, मध्य प्रदेश को हस्तांतरित किया गया है। देश के किसी भी राज्य में लागू करने के लिए पोर्टल को तैयार किया गया है।

भावी कार्य योजना :

- नागरिकों और शोध विद्वानों को लेखांकन जानकारी प्रदान करने के लिए इंटरफ़ेस।
- त्वरित और आसान डेटा प्रस्तुत करने के लिए मोबाइल ऐप।



पुरस्कार / प्रशंसा

साइबर सुरक्षा सलाह

अटल ई-गवर्नेंस राज्य पुरस्कार 2022-23 और 2023-24 (राजस्थान आईटी दिवस 27-28 मार्च, 2025 को प्रदान किया)



श्री शारुल खसरोना, वैज्ञानिक 'डी' को वेतन प्रबंधक, पी.आर.आई.वेतन प्रबंधक, एकाद नोडल खाते (एसएनए) के विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।



श्री अभय गुप्ता, वैज्ञानिक 'डी' को ई-जी.आर.एस, ई-खाता प्रसंस्करण और एजी को प्रस्तुत करने; ई-कुबेर, राजकोष, आरएसजीएस और एसएनए स्पर्श के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकास में योगदान हेतु सम्मानित किया गया।



"डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से खुद को बचाने के लिए, कभी भी संवेदनशील जानकारी साझा न करें। आधिकारिक चैनलों के साथ दावों को सत्यापित करें और अधिकारियों को सदिग्ध गतिविधि की सूचना दें।"

परियोजना लेन-देन सांख्यिकी



श्री शैलेन्द्र कुमार धनवारिया, डीआईओ, NIC हनुमानगढ़ को मानस ई-आरोप पोर्टल विकसित करने और जिले में चुनाव आईटी अनुप्रयोगों को लागू करने के लिए सम्मानित किया गया। श्री काना राम, डीएम, ने माननीय विधायक श्री गणेशराज बंसल और डीआईओ की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किया।



श्री सुशील कुमार अग्रवाल, डीआईओ, एनआईसी टॉक को एआई तकनीक के साथ शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई/विद्यार्थी पोर्टल में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। श्री कन्हैया लाल, माननीय मंत्री, पी.एच.ई.डी. राजस्थान ने श्रीमती सोम्या झा, जिला कलेक्टर व श्री विकास सांगवान, एसपी टॉक की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किया।



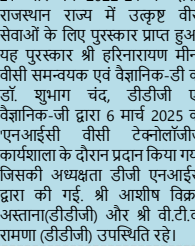
SN	Project	Number of Transactions			Total Trans.
		Jan-25	Feb-25	Mar-25	
1	DBT through Pay Manager	16428166	15802601	22662304	54893071
2	DILRMP ROR	1696084	1658480	13731471	17086035
3	Shala Darpan	4064855	8196193	8765332	21026380
4	IFMS - Rajkosh Challans	1352170	1230184	1715562	4297916
5	eGras	1177345	1060254	1514594	3752193
6	IFMS - Rajkosh Bills	277736	391476	562282	1231494
7	Pay Manager Other Bills	201983	230441	395062	827486
8	Registration and Stamps	215390	175472	201107	591969
9	E-Transport	12719	102971	116930	232620
10	Vehicle Registration	66706	48184	59288	174178



श्री कमल नयन पांडिया, डीआईओ, एनआईसी प्रतापगढ़ को श्री हेमन्त मीना, माननीय कैबिनेट मंत्री, सरकार द्वारा प्रतापगढ़ जिले में डिजिटल और साइबर जागरूकता अभियान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष, डीएम व एसपी प्रतापगढ़ भी उपस्थित थे।



श्री 'दिलीप जैन', डीआईओ एनआईसी बाड़मेर को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय समारोह में सीईओ, जिला परिषद, से चुनाव गतिविधियों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया, साथ ही उन्हें ई-आर.ओ.एट, सर्विस वोटर और एनजीआरएस पोर्टल के लिए नोडल अधिकारी आईटी के रूप में पर्यवेक्षण व निगरानी करने का दायित्व भी सौंपा गया।



एनआईसी राजस्थान को वर्ष 2020-21 और वर्ष 2022-24 के दौरान राजस्थान राज्य में उत्कृष्ट वीसी सेवाओं के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार श्री हरिनारायण मीना, वीसी समन्वयक एवं वैज्ञानिक-डी को डॉ. शुभांग चंद, डीडीजी एवं वैज्ञानिक-जी द्वारा 6 मार्च 2025 को 'एनआईसी वीसी टेक्नोलॉजीज' कार्यशाला के दौरान प्रदान किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीजी एनआईसी द्वारा की गई। श्री अशोष विक्रम अस्ताना(डीडीजी) और श्री वी.टी.वी. रामणा (डीडीजी) उपस्थिति रहे।

प्रौद्योगिकी वार्ता: सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 और इसका आयोजन



सुरक्षित इंटरनेट दिवस ऑनलाइन सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव है। यह हर साल फरवरी महीने के दूसरे मंगलवार को लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह सभी के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल है, जो जिम्मेदार, सम्मानजनक, आलोचनात्मक और रचनात्मक प्रौद्योगिकी उपयोग पर केंद्रित है।

सुरक्षित इंटरनेट दिवस का उद्देश्य उभरते ऑनलाइन मुद्दों और वर्तमान चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। इस वर्ष इसे मंगलवार 11 फरवरी, 2025 को "एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए" थीम के तहत मनाया गया और सभी हितधारकों से इंटरनेट को सभी के लिए सुरक्षित और बेहतर स्थान बनाने के लिए एक साथ जुड़ने का आह्वान किया गया। इसका फोकस ऑनलाइन धोखाधड़ी, घोटाले, साइबर खतरे, साइबर स्वच्छता, डिजिटल गिरफ्तारी आदि पर था व युवा लोग खुद को, दूसरों को किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं और उनके लिए किस तरह की सहायता उपलब्ध है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस के लिए प्रतिज्ञा - "मैं चोरी नहीं करूंगा, हक नहीं करूंगा, किसी और के खातों में सेंध नहीं लगाऊंगा या बिना अनुमति के दूसरों की सामग्री का उपयोग नहीं करूंगा। मैं अपने पासवर्ड सुरक्षित रखूंगा और अच्छी नेट सुरक्षा का अभ्यास करूंगा।"

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तत्वावधान में, एनआईसी मुख्यालय की पहल पर 11 फरवरी 2025 को पूरे देश में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एनआईसी राज्य केंद्र, जयपुर एवं सभी जिला केंद्रों ने सक्रिय भागीदारी के साथ विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित कीं। राजस्थान में, एनआईसी राज्य केंद्र जयपुर द्वारा सचिवालय, पुलिस अकादमी, जनगणना विभाग, भामाशाह राज्य डेटा केंद्र (BSDC), वित्त भवन तथा NIC VDN सहित कई स्थानों पर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं। साथ ही, जन जागरूकता हेतु बैनर और स्टैंडी विभिन्न वांछित स्थानों पर प्रदर्शित किए गए। जिला स्तर पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (DIOs) ने जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शिक्षा, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इंजीनियरिंग कॉलेज, उच्च शिक्षा संस्थान, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, केन्द्रीय विद्यालय, स्काउट व सीएससी जैसे प्रमुख विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की। आयोजन से पूर्व संबंधित विभागों के साथ तैयारी बैठकें आयोजित की गईं और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्हें प्रस्तुति, बैनर, कार्यक्रम रिपोर्टिंग प्रारूप आदि की सॉफ्टकॉपी भी उपलब्ध कराई गई। जिला स्तर पर, सूचनात्मक प्रस्तुतियों और वीडियो के माध्यम से कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें कलेक्टर, जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर बैनर लगाकर जन जागरूकता बढ़ाई गई। पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सरकारी कॉलेजों, ITI आदि ने भी अपने स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित कीं। जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष रूप से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इनमें छात्रों को साइबर खतरों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और घोटालों के प्रति सतर्क रहने तथा उनसे बचाव के उपायों और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग हेतु साइबर स्वच्छता अपनाने के विषय में जागरूक किया गया। इस पहल के अंतर्गत 500 से अधिक स्थानों को कवर किया गया और 1,30,000 से अधिक प्रतिभागियों तक पहुंच बनाई गई। इसमें राज्य और जिलों के 150 से अधिक स्कूल, अनेक संस्थान, संगठन और सरकारी विभाग शामिल थे। गतिविधियों में शैक्षिक बैनर, ब्रोशर, पैम्फलेट का वितरण, वेबिनार और जागरूकता सर्तों का आयोजन शामिल था। राजस्थान के प्रमुख व स्थानीय समाचार पत्रों ने भी इन आयोजनों को व्यापक रूप से सम्पादित किया, जिससे सुरक्षित इंटरनेट के महत्व व जन-जागरूकता को और बल मिला।



श्री हेमन्त मेहता
डीआईओ एवं वैज्ञानिक-ई,
एनआईसी जिला केंद्र,
बांसवाड़ा, राजस्थान



एनआईसी राजस्थान द्वारा सुरक्षित इंटरनेट दिवस समारोह की गतिविधियाँ

Published By

संरक्षक
श्री जे. के. वर्मा, एस. आई. ओ. राजस्थान

Editorial Board

श्री मुकेश कुमार झा, वैज्ञानिक-एफ'
श्री अमित अग्रवाल वैज्ञानिक-एफ'
श्री दिलीप जैन, वैज्ञानिक-ई'
श्री विनोद कुमार शर्मा, वैज्ञानिक-ई'
श्री हेमन्त मेहता, वैज्ञानिक-ई'
श्री मनीष कुमार शर्मा, वैज्ञानिक-सी'
श्रीमती सोनिया तोमर, एसटीए-ए'

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
राजस्थान राज्य केंद्र
8318, उत्तर-पश्चिम खंड
सरकारी सचिवालय,
सी-स्क्रीम, जयपुर, 302005
0141-2227992
ईमेल: sioraj@nic.in
वेबसाइट: https://raj.nic.in

सेवानिवृत्ति



श्री प्रसून जैन, वैज्ञानिक 'एफ'
जन्म तिथि: 14-04-1967
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि: 19-12-1991
कार्यभार ग्रहण किया: वैज्ञानिक अधिकारी
सेवानिवृत्ति की तिथि: 07-02-2025
सेवानिवृत्ति: राजस्थान राज्य केंद्र

शिक्षा: बी.टेक (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग)
पदस्थापन स्थान: DIO बारां (1991-1995), DIO पाली (1995-1996), हार्ड कोर्ट
बेंच जयपुर (1996-2016), एनआईसी स्टेट सेंटर (2016-2025)
परियोजना संचालन: कार्यकाल के दौरान बारां और पाली जिलों में सभी
एनआईसी परियोजनाओं का संचालन। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में
न्यायालय कम्प्यूटीकरण के लिए राज्य समन्वयक। राजस्थान राज्य केंद्र में राशन
कार्ड, राजफेड, ई-श्रम, आई.एच.आर.एम.एस, एग्रीसेन्ट, पंचायतीराज जैसी
परियोजनाओं के लिए योगदान दिया। जीई.एम अध्यक्ष, स्थानांतरण और
अवसंरचना समिति के सदस्य और 2018 से सेवानिवृत्ति तक ए.एस.आई.ओ रहे।

एनआईसी में काम करने का एक अद्वितीय अनुभव मेरे रिटायरमेंट के बाद
भी लंबे समय तक मेरे साथ रहेगा। एनआईसी में काम करना मेरे लिए बहुत
गर्व की बात रही है क्योंकि यह एक प्रतिष्ठित संगठन है जो एक स्वस्थ कार्य
वातावरण और सीखने और विकसित होने के अंतर्हीन अवसर प्रदान करता
है। मैं अपने सभी सहकर्मियों को अपने पूरे सफ़र में उनके अटूट सहयोग
और साथ के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुझे हमेशा एनआईसी में मदद
करने वाले हाथ मिले हैं और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा।
मैं एनआईसी और मेरे सभी सहकर्मियों की आने वाले वषों में निरंतर
सफलता की कामना करता हूँ।
~प्रसून जैन

नव नियुक्त वैज्ञानिक अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन



श्री विकास कुमार
एनआईसी जिला केंद्र बाड़मेर
कार्यग्रहण तिथि - 12-03-2025



श्री दिवेश
एनआईसी जिला केंद्र जोधपुर
कार्यग्रहण तिथि - 17-03-2025



श्री कुंतिक जैन
एनआईसी जिला केंद्र चित्तौड़गढ़
कार्यग्रहण तिथि - 20-03-2025

राजस्थान में / से स्थानांतरण



श्री विकास कुमार, (वैज्ञानिक-सी)
एनआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली
से
एनआईसी राज्य केंद्र,
जयपुर



श्री ललित गोयल, (वैज्ञानिक-एफ)
एनआईसी राज्य केंद्र जयपुर
से
एनआईसी मुख्यालय,
नई दिल्ली



श्रीमती सुनीता जैन, (वैज्ञानिक-एफ)
एनआईसी राज्य केंद्र जयपुर
से
एनआईसी मुख्यालय,
नई दिल्ली